श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील: महोदय, मैं खंडवा जिले के बारे में बताना चाहता हूं । खंडवा जिले की आलमगीर तहसील में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो मुख्य रास्ते से जुड़े नहीं हैं । मैं वहां गया था जो मुझे 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जिन एरियाज़ की कनेक्टिविटी नहीं है, पहले उनको जोड़ा जाए।

Floating of equity by NTPC

*562. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether National Thermal Power Corporation proposes to float a certain quantity of its equity in the primary market;

(b) if so, the details in this regard; the anticipated financial inflow through such offerings and whether such offerings would be in conformity with SEBI guidelines; and

(c) the projects and proposals to which the earnings from dispensed equity would be channeled?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) In order to meet the fund requirements for its capacity addition programme, National Thermal Power Corporation (NTPC) is contemplating a proposal to augment its share capital base by way of Initial Public Offering (IPO).

The detailed proposal has not yet been made available to Government.

SHRI JANARDHANA POOJARY: The profit of NTPC is Rs. 3574 crores and the Government is receiving about Rs. 400 crores. Unfortunately, the NTPC is trying to disinvest its shares. It has been reported in the newspapers that a letter has been written to the Disinvestment Ministry by the nodal Ministry stating that at this juncture it would amount to under-selling of Government security in the company and will be counter-productive to its capacity-addition programme in the coming years. This is the observation of the nodal Ministry. Is it a fact that your nodal Ministry has written a letter to the Disinvestment Ministry? What is the reaction of the Disinvestment Ministry? What are the details?

श्री सभापति: माननीय सदस्य एक बात बता दें कि अखबार में जिस समाचार के आधार पर आपने प्रश्न पूछा है, क्या आप उसको सब्स्टेनशिएट करते हैं?

SHRI JANARDHANA POOJARY: I beg your pardon, Sir.

श्री सभापति: जो न्यूज़ आई है, जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप उसको सब्स्टेनशिएट करते हैं?

SHRI JANARDHANA POOJARY: He can say that it is wrong.... *(Interruptions)*. I was also in the Ministry. I have been in Parliament for the last 25 years.

श्री सभापति: मिनिस्ट्री का क्या रियेक्शन है बताइए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: महोदय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। NTPC के डिसइन्वैस्टमेंट का कोई प्रस्ताव नहीं है।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Has your Ministry written a letter? You can say, 'yes', or, 'no'...*(Interruptions)*...

श्री अनन्त गंगाराम गीते: महोदय, मैंने जवाब दे दिया है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Hasn't a letter been written? ...*(Interruptions)* ...

श्री सभापति: मैंने इसीलिए कहा था कि समाचारपत्रों की जानकारी के आधार पर माननीय सदस्य अगर क्वेश्चन पूछें तो उसको सब्स्टेनशिएट भी करें।

SHRI JANARDHANA POOJARY: No, Sir. I am asking a simple question: Has the Government written a leter to the NTPC? He can say 'no' or 'yes'...*(Interruptions)* ...He is avoiding ... *(Interruptions)* ...

श्री सभापति: मंत्री जी, बताइए।

SHRI JANARDHANA POOJARY: He can say 'yes' or 'no' ... *(Interruptions)* ... You are a good administrator. Whether a letter has been written or not, he can say. Has the nodal Ministry written a letter or not?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति महोदय, NTPC के डिसइन्वैस्टमेंट का कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके जवाब में जो वास्तविक उत्तर है, वह देना मेरी जिम्मेदारी है। सदस्य जो चाहें, वह जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, are you satisfied with the answer? I am not. I wanted to know whether a letter has been written by

the Nodal Ministry stating therein that the said proposal is counter productive and they should not sell it. Sir, the Minister can very well say whether he has written a letter or not. *(Interruptions)* Sir, you have to protect us. *(Interruptions)* I have put such a simple question. *(Interruptions)* Sir, we need your protection. Sir, let the Minister deny that he has not written a letter. *(Interruptions).*

श्री संतोष बागड़ोदिया: लैटर दिया है या नहीं दिया, बस इतना ही तो पूछा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है कि लैटर लिखा है या नहीं है। वह कहते हैं कि नहीं आता है तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री संतोष बागड़ोदिया: यह तो सप्लीमेंटरी है।

श्री सभापति: सप्लीमेंटरी का मतलब यह नहीं है कि प्रश्न के परव्यू के बाहर आप क्वेश्चन करते रहें।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, my submission is very simple. There is a proposal to disinvest some shares. Now, the question is, whether the Government has written a letter to the NTPC in the national interest stating therein that 'do not sell the shares since this proposal is counter productive.' I would like to know whether the Minister has written that letter or not. *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you say: "Yes or no". Let him say that. *(Interruptions).*

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I have got a second supplementary.

MR. CHAIRMAN: What is your second supplementary?

श्री संजय निरुपम: आपका प्रश्न सिर्फ एन.टी.पी.सी. के डिसइनवैस्टमेंट का था कि ... (**व्यवधान**) ... सरकार का कहना है कि नहीं, तो और क्या सप्लीमेंटरी पूछेंगे?

SHRI JANARDHANA POOJARY: Mr. Sanjay Nirupam, you are also for disinvestment. *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: It does not come within the purview of this question.

श्री सभापति: यह क्वेश्चन के परव्यू में नहीं आता है। ...(**व्यवधान**)... नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। संतोष जी, आप पूछिए। *(Interruptions).*

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I am putting my second supplementary.

MR. CHAIRMAN: What is your second supplementary? You have already put four questions.

SHRI JANARDHANA POOJARY: But, Sir, I have not received any reply to my questions from the hon. Minister. You know, Sir, the problem is very acute, particularly in some of the States, where the drought is there. For instance, in Rajasthan and Karnataka, the position is very bad now. Small farmers, who are having one or two acres of land, are facing great hardships. Since this subject is in the Concurrent List, I would like to know whether the Central Government is thinking of sharing the subsidy given by the State Governments to the drought-affected States.

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, सदस्य की भावना से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि आज सूखे की स्थिति कई राज्यों में है और राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे नये प्रोजैक्ट को लगाएं। मैं कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं। 1990 में एन.टी.पी.सी. ने मैंगलोर में 1000 मैगावाट का थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट लगाने का एक प्रस्ताव दिया था, प्रपोज़ल किया था लेकिन राज्य सरकार ने उसे सहमति नहीं दी और राज्य सरकार ने वह प्रोजैक्ट एक निजी संस्था को दिया है। इसके अलावा एन.एच.पी.सी. ने अभी एक एमओयू भी कर्नाटक गर्वनमेंट के साथ साइन किया है। एन.एच.पी.सी. कृष्णा नदी पर 800 मैगावाट का एक प्रोजैक्ट लगाना चाहती है लेकिन राज्य सरकार में सिंचाई के लिए पानी देना या पॉवर के लिए पानी देना, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर विवाद चल रहा है। जो सहयोग चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारें जो भी सहयोग चाहती हैं, वह दिया जाएगा।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, my question is quite different.

श्री संतोष बागड़ोदिया: चेयरमैन साहब, एन.टी.पी.सी. एक नवरत्न यूनिट है। इनकी ऐफीशिएंसी वर्ल्ड में कम्पेयरेबल है, वन ऑफ दी बैस्ट है। उसके बाद भी इनके पास इतना शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्यों हो रहा है? इस डिटेल्स में आप कभी गये हैं? हो सकता है कि आपकी टैरिफ पॉलिसी गलत हो या आपका इरादा कुछ और हो कि बैक डोर से आप थोड़े बहुत शेयर्स बाजार में बेच दें और धीरे धीरे ऐसी पारस्थिति आ जाए कि इन्हें प्राइवेटाइज़ करने का इरादा हो। इन दोनों में से कौन सी बात सही है, वह बता दें।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, एन.टी.पी.सी. की वित्तीय स्थिति अच्छी है और 10th Plan में एन.टी.पी.सी. को जो लक्ष्य दिया गया है, वह 9,000 मेगावॉट का लक्ष्य दिया गया है। इसे पूरा करने के लिए लगभग 60,000 करोड़ की आवश्यकता है। यदि 70 और 30 के रशियो में हम देखते हैं तो 70 प्रतिशत हम ऋण के रूप में जुटा सकते हैं और 30 प्रतिशत तो एन.टी.पी.सी. को वहां पर जुटाना है और उसमें से लगभग 10,000 करोड़ आज एन.टी.पी.सी. ने अपने बल पर जुटाए

हैं। बाकी जो बचे हुए 9,000 करोड़ हैं, उसके लिए एन.टी.पी.सी. प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने, हमने जो 10th Plan का प्रोग्राम किया है, उसके अंदर भी लगभग 3,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यदि एन.टी.पी.सी. चाहे तो बजटरी सपोर्ट उसको मिल सकता है और एन.टी.पी.सी. की स्थिति अच्छी है। इसलिए निजीकरण का, प्राइवेटाइज़ेशन का या डिसइनवेस्टमेंट का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के सामने नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि एन.टी.पी.सी. अपनी पावर जेनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है और फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने पर वह विचार कर रहा है ताकि शेयर कैपिटल बेस को बढ़ाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एन.टी.पी.सी. की बहुत बड़ी धनराशि राज्यों के ऊपर अथवा कुछ संस्थाओं के ऊपर बकाया है? यदि बकाया है तो वह धनराशि कुल कितनी है और क्या यह भी सच है कि यदि पूरी बकाया धनराशि की वसूली कर ली जाए तो फंड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है और एन.टी.पी.सी. की पावर जेनरेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है?

श्री सभापति: यह कवेश्चन इसके परव्यू में नहीं आता है, I won't allow. Next question.

संघ-लोक-सेवा-आयोग में परीक्षाओं और साक्षात्कारों का माध्यम

*563. **श्री बालकवि बैरागी : क्या कार्मिक**, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कारों का माध्यम क्या है;

(ख) राजभाषा हिन्दी के पूर्ण प्रयोग में हुई प्रगति और तत्संबंधी बाधाएँ क्या-क्या हैं; और

(ग) संघ-लोक-सेवा-आयोग के कार्यकरण में उसका पूर्ण रूप से प्रयोग कब से आरम्भ किया जाएगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम की भाषा दर्शाने वाला विवरण, विवरण-I के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)। जहाँ तक साक्षात्कारों के माध्यम की भाषा का संबंध है, सिविल सेवाओं की परीक्षा से संबंधित साक्षात्कार के सिवाय अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कार, सामान्यत: अंग्रेज़ी-भाषा के माध्यम से किए जाते हैं। सिविल सेवाओं की परीक्षा में बैठने वाले उन उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार अंग्रेज़ी-भाषा के माध्यम से ही दिया जाना